



2026:AHC:5216

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 33299/ 2025

इसरार उद्दीन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: मोहम्मद इमरान खान

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद इमरान खान तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री याज्ञवल्क पांडेय को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

यह जमानत आवेदन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत अभियुक्त-आवेदक इसरार उद्दीन की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रकरण अपराध संख्या 0401 सन् 2024, धारा 318(4), 316(5), 61(2) बी.एन.एस. 2023 तथा धारा 66 आई.टी. अधिनियम, थाना सेक्टर-63, जनपद गौतम बुद्ध नगर में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहाई की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है और वह 06.08.2025 से कारागार में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 27.08.2025 को आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है तथा न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। आवेदक के विरुद्ध किसी अंदरूनी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत नहीं है। यह भी कहा गया कि सह-अभियुक्त हरीशपाल भाटी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.09.2025 को विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 9181/2015 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का कोई आपराधिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इतिहास नहीं है और उसके न्याय से फरार होने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गई।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत का विरोध किया, किंतु इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि सह-अभियुक्त हरीशपाल भाटी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, साक्षियों को प्रभावित करने की आशंका तथा प्रथम दृष्टया मामले को दृष्टिगत रखते हुए, किंतु प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जमानत का मामला बनता है।

अतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त-आवेदक इसरार उद्दीन, उपर्युक्त प्रकरण अपराध संख्या में, न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों को प्रभावित/धमकाने का प्रयास नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

दिनांक: 8 जनवरी, 2026

एम.एन./-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।